भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2673

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह

2673. डॉ. राजकुमार सांगवान:

श्रीमती डी. के. अरुणा:

श्रीमती बिजुली कलिता मेधी:

श्री बंटी विवेक साहू:

श्री आशीष दुबे:

श्री सुनील कुमार:

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को गुवाहाटी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संवितरित और बकाया ऋणों की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने और बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों का समय पर संबद्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) ऋण प्रवाह और ई-भुगतान की निगरानी के लिए विकसित किए गए एनआरएलएम एसएचजी-बैंक लिंकेज पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) में कमी सुनिश्चित करने और ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) जबलपुर में पंजीकृत और कार्यशील स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी है; और

(च) बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत प्रारंभ से लेकर अब तक महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को संवितरित और बकाया ऋणों की कुल राशि, जिसमें गुवाहाटी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, इस प्रकार है: -

करोड़ रु में

क्र.सं.	**विवरण(प्रारंभ से लेकर अब तक)**	**संवितरित ऋण की राशि**	**बकाया ऋणों की कुल राशि**
1.	देश में	11,86,517.65	3,13,392.53
2.	एएसआरएलएम के तहत एसएचजी को संवितरित ऋण की राशि (गुवाहाटी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित)	22,192	9,155
3.	गुवाहाटी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र	1781.50	655.75

ख) ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने और बैंकों के साथ एसएचजी का समय पर जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल इस प्रकार हैं: -

i. एनआरएलएम हर वर्ष एसएचजी-बैंक लिंकेज पर मास्टर परिपत्र जारी करने में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ मिलकर निकटता से काम करता है, जो एसएचजी सदस्यों के वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाता है, विनियमित करता है और बढ़ावा देता है।

ii. एसएचजी को ऋण देने के मानदंडों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ निरंतर मिलकर कार्य करना ताकि एसएचजी क्रेडिट लिंकेज में देरी कम हो सके।

iii. ब्याज दर को किफायती बनाने के लिए पात्र एसएचजी को ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करता है।

iv. एसएचजी सदस्यों के लिए विभिन्न बैंक उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, ऋण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया और इसके उपयोग के लिए नियमित वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण आयोजित करता है।

v. बैंक और समुदाय के बीच अंतिम मील के अंतर को पाटने और प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए स्थानीय प्रशिक्षित एसएचजी सदस्यों की तैनाती।

vi. समुदाय-आधारित पुनर्भुगतान तंत्र (सीबीआरएम) के माध्यम से ऋण पुनर्भुगतान की निगरानी।

vii. ऋण के सुचारू प्रसंस्करण के लिए बैंक प्रबंधकों का नियमित अभिविन्यास।

ग) ऋण प्रवाह और ई-भुगतान की निगरानी के लिए विकसित एनआरएलएम एसएचजी-बैंक लिंकेज पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य हैं:

i. सभी राज्यों और बैंकों में एसएचजी क्रेडिट लिंकेज पर नज़र रखना।

ii. डेटा बैंकों द्वारा पोर्टल में अपलोड किया जाता है, जो सीधे कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) से प्राप्त होता है।

iii. बैंक-वार और राज्य-वार प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी के लिए हितधारकों को डैशबोर्ड और विश्लेषण प्रदान किए जाते हैं।

iv. सटीकता सुनिश्चित करने और दोहराव को रोकने के लिए डेटा सत्यापन जांच करना।

v. राज्यवार और बैंकवार एनपीए स्थिति का पता लगाकर बेहतर ऋण अदायगी अनुशासन को बढ़ावा देना।

vi. बैंक-वार और राज्य-वार प्रदर्शन।

vii. पारदर्शिता में सुधार और विभिन्न स्तरों पर एसएचजी को ऋण प्रवाह की निगरानी को मजबूत करना।

viii. उच्च गुणवत्ता, प्रामाणिक डेटा और प्रवृत्ति विश्लेषण के माध्यम से निर्णय लेने में सहायता करना।

ix. यह सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना कि सभी पात्र एसएचजी औपचारिक बैंकिंग से जुड़े हुए हैं।

घ) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में कमी को सुनिश्चित करने और ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए किए जा रहे उपाय निम्नलिखित हैं: -

i. सभी शाखाओं में समुदाय-आधारित पुनर्भुगतान तंत्र बनाना, जिसमें ग्राम संगठन (वीओ) और क्लस्टर-स्तरीय संघ (सीएलएफ) शामिल होंगे ताकि ऋण के उपयोग की निगरानी की जा सके और पुनर्भुगतान अनुशासन लागू किया जा सके।

ii. पुनर्भुगतान स्थिति का समाधान करने के लिए एसएचजी बैंक लिंकेज पोर्टल के माध्यम से राज्य-वार और बैंक-वार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की नियमित निगरानी करना।

iii. नियमित और समय पर ऋण पुनर्भुगतान का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाले एसएचजी के लिए ब्याज अनुदान का प्रावधान करना।

iv. उचित ऋण उपयोग और पुनर्भुगतान का पता लगाने पर एसएचजी का मार्गदर्शन करने के लिए बैंक सखियों द्वारा निरंतर सहायता करना।

v. विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और भारत सरकार की योजनाओं के बारे में एसएचजी सदस्य अवगत हैं यह सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता पर बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

ङ) डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत, जबलपुर में, कुल 10,917 एसएचजी का गठन किया गया है जो 1,32,336 ग्रामीण परिवारों (एचएचएस) को शामिल करते हुए कार्य कर रहे हैं। एसएचजी अनौपचारिक निकाय हैं इसलिए उनके लिए किसी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च) बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत, 40,243 एसएचजी में कुल 3,93,167 ग्रामीण परिवारों को संगठित किया गया हैं।

****